

आज का तापमान
22°C

सोना चांदी का रेट
सोना प्रति 10 ग्राम: 24 के 35,096.00
22 के : 32,160.00
चांदी प्रति किग्रा 43,100

करंसी

1-डालर	70.60
2-पाउन्ड	90.81
3-यूरो	79.72
4-आस्ट्रेलिया डालर	50.06

शेयर मार्केट

सेन्सेक्स	36,153.62
निफ्टी	10,831.40

गुर्जर आंदोलन पांचवें दिन भी जारी, रेल सेवा प्रभावित, इंटरनेट सर्विस बंद
जयपुर 12 फरवरी राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण के लिए आंदोलन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन के चलते गुर्जर बहुल जिलों में कई रेल व सड़क मार्ग बंद हैं। अनेक ट्रेन रद्द कर दी गई हैं या उनके मार्ग में बदलाव किया गया है हालांकि रविवार के बाद किसी तरह की अप्रति घटना का समाचार नहीं है।

कुछ अहम....

अखिलेश को हवाई अड्डे पर रोके जाने को मायावती ने बताया तानाशाही रवैया



लखनऊ 12 फरवरी बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इलाहाबाद जाते समय लखनऊ हवाई अड्डे पर मंगलवार को रोके जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। मायावती ने ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आज इलाहाबाद नहीं जाने देने कि लिये उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लेने की घटना अति-निन्दनीय व बीजेपी सरकार की तानाशाही व लोकतंत्र की हत्या की प्रतीक है। बीजेपी की केन्द्र व राज्य सरकार बीएसपी.सपा गठबंधन से इतनी ज्यादा भयभीत व बौखला गई है कि उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधि व पार्टी प्रोग्राम आदि करने पर भी रोक लगाने पर बह तुल गई है। अति दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी आलोचकतात्मक कार्रवाई का डट कर मुकाबला किया जायेगा।

जेटली का कांग्रेस पर हमला: बोले- डूबते राजवंश को बचाने के लिए और कितने झूठ

नई दिल्ली 12 फरवरी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर ब्लाॅग लिखकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जेटली ने अपने ब्लाॅग में लिखा कि आखिर एक डूबते राजवंश को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे उन्होंने कहा कि विश्व के ज्यादातर लोकतंत्रों में जो लोग झूठ के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वे खुद सामाजिक जीवन से गायब हो जाते हैं। जेटली ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बदलते सामाजिक.आर्थिक परिवेश में भी भारत में भी ऐसा ही होगा। जेटली ने कहा कि आधुनिक दुनिया में जितने भी राजनीतिक वंश हैं उनकी कुछ सीमाएं हैं। हमारा समाज अब इस तरह की व्यवस्था को पसंद नहीं करता है। आज लोग जवाबदेही और काबिलियत पर धरोसा रखते हैं। इसवह जेटली ने कहा कि ताजा झूठ राफेल संबंध में संसद में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट को लेकर फैलाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा,सौगातों की लगी झड़ी हर ईमानदार को चौकीदार पर विश्वास, जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है-पीएम मोदी



कुरुक्षेत्र, 12 फरवरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चार वर्षों के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों व कार्यों की जहां सराहना कर उनकी पूरी टीम की पीठ थपथपाई वहीं दूसरी ओर वर्ष 2014 में पार्टी द्वारा उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने उपरांत भूतपूर्व सैनिकों की रैली में वोट मांगने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए हरियाणा के लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने 2019 में होने वाले आगामी चुनाव में समर्थन के लिए हरियाणा की पावन धरमंनगरी कुरुक्षेत्र से आहवान किया। प्रधानमंत्री आज कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण स्वच्छ शक्ति 2019 का शुभारंभ करने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तरप्रदेश राजस्थान गुजरात मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश मेघालय तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव की स्वच्छता प्रेरकों को सम्मानित किया तथा इनके गांवों वासियों को भी नमन किया जिन्होंने महिला शक्ति का साथ देकर उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नारी शक्ति का यह समर्थन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इसी वर्ष 2 अक्टूबर को होने वाले 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत राष्ट्र को समर्पित करने के लक्ष्य को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि जब-जब वे हरियाणा के लोगों से आशिर्वाद लेने आते हैं उन्होंने तब-तब लक्ष्य को हासिल किया है चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात हो आयुष्मान भारत की बात या स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की बात हो या 2014 में रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन के वायदे की बात हो। उन्होंने कहा कि इसी धरती से उन्हें सफलता मिली है।

राफेल पर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस: राजनाथ



नई दिल्ली 12 फरवरी गुह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी कांग्रेस पर राफेल विमान सौदे के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुये इस पर चर्चा की उसकी मांग उकरा दी जिस पर कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया। सिंह ने सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यह इस मामले को उठाए जाने पर कहा कि राफेल पर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपना फैसला दे दिया है। इसलिए दुबारा चर्चा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा प्षिपक्ष के सदस्य बार-बार असत्य बोलकर उसे सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति जनता की आंखों में धूल झाँककर नहीं जनता की आंखों में आंखें डालकर होती है इनके जवाब से असंतुष्ट खड़गे ने कहा प्षिपक्ष के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है। उन्होंने इस पर सदन में बयान भी नहीं दिया है। इसलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले खड़गे ने आरोप लगाया था कि राफेल सौदे में 33 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा इसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राफेल से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैंग की रिपोर्ट सदन में पेश करने से पहले ही मीडिया में लीक करायी गई है जिससे साबित होता है कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जब खड़गे अपनी बात रख रहे थे उस समय सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर-जोर से हंगामा करने लगे।

रॉबर्ट वाड्रा से करीब 3 घंटे और उनकी मां से डेढ़ घंटे तक ईडी ने की पूछताछ



जयपुर 12 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बीकानेर जिले में कथित जमीन घोटाले के संबंध में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मीरीन वाड्रा से पूछताछ की। वाड्रा से यह पूछताछ करीब तीन घंटे तक चली जिसमें उनको मां मीरीन करीब डेढ़ घंटे में ही ईडी कार्यालय से बाहर आ गई थीं। वाड्रा अपनी मां मीरीन के साथ सुबह साढ़े 10 बजे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। लगभग डेढ़ घंटे बाद मीरीन वाड्रा ईडी कार्यालय से चली गईं वहीं वाड्रा दोपहर डेढ़ बजे बाहर निकले। सूचना है कि वाड्रा भोजनावकाश के बाद वापस आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। सुबह कांग्रेस महासचिव व वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी ईडी कार्यालय तक उन्हें छोड़ने आई थीं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाड्रा प्रियंका व मीरीन एक ही वाहन से शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वाड्रा जयपुर में ईडी के सामने पहली बार हाजिर हुए हैं। जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना मिलने पर सेना ने यह ऑपरेशन चलाया था। इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया

करोल बाग के होटल अर्पित में भीषण आग, 17 की मौत, सीएम ने किया 5 लाख रुपये की सहायता राशि का एलान



नई दिल्ली 12 फरवरी दिल्ली के करोल बाग में स्थित अर्पित होटल में मंगलवार तड़के भीषण आग गई। आग की चपेट में आने से एक बच्चे सहित 17 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से झुलसे हैं। वहीं फायरकर्मियों ने अबतक करीब 35 लोगों को बाहर निकाल दिया है। हालांकि अभी कुछ अन्य लोगों के फंसे होने की सूचना है। राहत व बचाव कार्य जारी है। आग लगने के पीछे के कारणों का अबतक कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी तक 13 मृतकों को आरएमएलए 2 को लोडी हार्डिंग और 2 को बीएलके अस्पताल में लाया जा चुका है। इसके अलावा कुछ घायल गंगाराम अस्पताल भी ले जाये गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर दुःख व्यक्त किया है और मरने वाले लोगों के परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिंसोदिया ने बताया है कि उनकी सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया था जिसको रद्द कर दिया गया है दिल्ली के मंत्री सर्येंद्र जैन ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने आग की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जैन ने लापरवाही का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ फर्जी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा सत्रह लोग मारे गए हैं और दो अन्य घायल हुए हैं। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई। दिल्ली के होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बालन मणि ने कहा सभी मानदंडों का पालन यहां किया गया था

पुलवामा में दो जवान शहीद, दो आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी



जम्मू 12 फरवरी पुलवामा जिले के रबीपोरा इलाके में मंगलवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं। समाचार भिजवाए जाने तक दो आतंकी भी ढेर किए जा चुके थे। मरने वाले आतंकियों में एक अल बद्र का कमांडर भी है। यह मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई थी। जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना मिलने पर सेना ने यह ऑपरेशन चलाया था। जिसके बाद आतंकियों ने खुद को

स्मृति ने राहुल पर साधा निशाना, कहा- पीएम पर आक्षेप लगाने का उतावलापन



हैदराबाद 12 फरवरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि गरीबों को लूटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कैसे कर सकते हैं। ईरानी ने यह भी सवाल किया कि जो भ्रष्टाचार में लिस थे।

पीएम मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है जनता: शाह



अहमदाबाद 12 फरवरी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जनता का जबर्दस्त समर्थन होने का दावा करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत के एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव एक अहम कदम हैं। शाह ने मोदी का मुकाबला करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन करने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन केवल राज्य स्तर के

राहुल गांधी का दावा: अनिल अंबानी के लिए बिचौलिया का काम कर रहे हैं पीएम मोदी



नई दिल्ली 12 फरवरी राफेल मामले में सामने आई एक नई मीडिया रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्योगपति अनिल अंबानी के बिचौलिया की तरह काम करने और सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री ने जो किया है वो देशद्रोह है। गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए मोदी पर अपराधिक कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। उन्होंने यह सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री के फ्रेंड्स दौरे से पहले अंबानी को कैसे पता चल गया था कि सौदा होने वाला

संसद के केंद्रीय कक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र का हुआ अनावरण सार्वजनिक जीवन की पाठशाला थे अटल बिहारी वाजपेयी - कोविंद



नयी दिल्ली 12 फरवरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद तैलचित्र का अनावरण किया और कहा कि वाजपेयी सार्वजनिक जीवन की पाठशाला थे जिन्होंने दलगत राजनीति के बीच स्वयं को सदा संकीर्णता से ऊपर रखा और राष्ट्रसेवा के भाव से काम किया। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा भारतीय राजनीति के महानायकों में अटल जी को हमेशा याद किया जाएगा। राजनीति में विजय और पराजय को स्वीकार करने में जिस सहजता और गरिमा का परिचय उन्होंने दिया है वह अनुकरणीय है। वे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य की

राफेल विवाद: रिलायंस डिफेंस की सफाई, एयरबस के साथ सहयोग को लेकर किया गया था इमेल



नई दिल्ली 12 फरवरी रिलायंस डिफेंस ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर अपने नए आरोपों में जिस कथित ईमेल का हवाला देते हुए प्रस्तावित सहमति पत्र का जिक्र किया है वह एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ उसके सहयोग के संदर्भ में था और उसका युद्धक विमान के ठेके से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल विमान सौदे में अनिल अंबानी का बिचौलिया बन कर देशद्रोह और शासकीय गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने एक ईमेल का हवाला देकर दावा किया कि कारोबारी को भारत और फ्रेंस के बीच सौदा होने से पहले ही इसके बारे में पता था। परिलायंस डिफेंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस कथित ईमेल का संदर्भ दिया जा रहा है वह मेक इन इंडिया के तहत नागरिक एवं रक्षा हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के बारे में एयरबस और रिलायंस डिफेंस के बीच हुई चर्चा।

संपादकीय



बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की यात्रा का चीन ने विरोध जताया है। चीन ने कहा है कि भारतीय नेतृत्व को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए, जिससे सीमा विवाद जटिल हो जाए। चीन का यह कदम भारत पर सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। भारत को चीन की परवाह किए बिना अपना काम और राज्यों को उन्नत करने का दायित्व निभाते रहना चाहिए।

चीन की धमकियों का करारा जवाब

बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के दौरे पर थे। वहां मोदी ने अरुणाचल को देश की सुरक्षा का द्वार, अस्था का प्रतीक और उगते सूरज की भूमि बताते हुए कहा कि यह प्रदेश हमारे संकल्प को मजबूती देता है। लोग यहां एक-दूसरे का 'जय हिंद' कहकर अभिवादन करते हैं। मैं उनके इस देशप्रेम को सलाम करता हूँ। इस पर चीन की त्वीरियां चढ़ गईं। उसने विरोध करते हुए कहा है कि भारतीय नेतृत्व को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए, जिससे सीमा विवाद जटिल हो जाए। दूसरी तरफ भारत ने चीन की आपत्ति पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए अरुणाचल को देश का अभिन्न और अभिभाज्य हिस्सा बताया है। चीन ने इसी तरह 2017 में भारत में तैनात अमेरिका के रजदूत रिचर्ड वर्मा के अरुणाचल प्रदेश जाने पर न केवल आपत्ति जताई थी, बल्कि बुरे नतीजे भुगतने की धमकी भी दी थी। हालांकि, भारतीय संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में इन आपत्तियों का कोई औचित्य नहीं है। चीन ने यह एताराज इसलिए दर्ज करवाया है, जिससे दुनिया को यह अहसास होता रहे कि अरुणाचल विवादित क्षेत्र है। इससे पहले भी मोदी जब अरुणाचल गए थे, तब भी चीन ने आपत्ति जताई थी।

चीन की ओर से भारत की चुनौती लगातार बढ़ रही है। दरअसल चीन भारत के बरखा बहुरूपिया का चोला ओढ़े हुए है। एक तरफ वह पड़ोसी होने के नाते दोस्त की भूमिका में पेश आता है, पंचशील का राग अलापता है और व्यापारी तक बन जाता है। किंतु पंचशील समझौते के सिद्धांतों का उल्लंघन का आदी वह बरामा की हद पार कर गया है। कितनी भी नरमी से भारत पेश आए चीन का मुखौटा दुश्मनी का ही दिखाई देता है, जिसके चलते वह पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक देता है। अरुणाचल को अपने नक्सों में शामिल कर लेता है और अपनी वेबसाइट पर भारतीय नक्सों से अरुणाचल को गायब कर देता है। साथ ही उसकी यह मंशा भी रहती है कि भारत विकसित न हो, उसके दक्षिण एशियाई देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत न हों और न ही चीन की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस दृष्टि से वह पीओके, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल में अपनी नापक मौजूदगी दर्ज कराकर भारत को परेशान करता रहता है।

दरअसल, चीन का लोकतांत्रिक स्वांग उस सिंह की तरह है जो गाय का मुखौटा ओढ़कर धूर्तता से दूसरे प्राणियों का शिकार करता है। इसका नतीजा है कि चीन 1962 में भारत पर आक्रमण करता है और पूर्वोत्तर

सीमा में अक्सर चिन की 38 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प लेता है। बावजूद अरुणाचल की 90 हजार वर्ग किमी पर दावा भी जताता है। कैलाश मानसरोवर जो भगवान शिव के आराध्य स्थल के नाम से हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में दर्ज है, सभी ग्रंथों में इसे अखंड भारत का हिस्सा बताया गया है। लेकिन भगवान भोले भंडारी अब चीन के कब्जे में हैं। यही नहीं गूगल अर्थ से होड़ बरते हुए चीन ने एक ऑनलाइन मानचित्र सेवा शुरू की है, जिसमें भारतीय भू-भाग अरुणाचल और अक्सर चिन को चीन ने अपने हिस्से में दर्शाया है। विश्व मानचित्र खंड में इसे चीनी भाषा मंदारिन में दर्शाते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताया गया है, जिस पर चीन का दावा पहले से ही बना हुआ है।

यहां गौरतलब है कि साम्यवादी देशों की हड़प नीति के चलते ही छोट सा देश चेकोस्लोवाकिया बर्बाद हुआ। चीनी दखल के चलते बर्बादी की इसी राह पर नेपाल है। पाकिस्तान में भरपूर निवेश करके चीन ने मजबूत पैठ बना ली है। बांग्लादेश और श्रीलंका को भी वह बरगलाने में लगा है। ऐसा करके वह सार्क देशों का सदस्य बनने की फिराक में है। इन कूटनीतिक चालों से इस क्षेत्र के छोटे-बड़े देशों में उसका निवेश और व्यापार तो बढ़ेगा ही सामरिक भूमिका भी बढ़ेगी। यह रणनीति वह भारत से मुकामले के लिए रच रहा है। चीन की यह दोगली कूटनीति तमाम राजनीतिक मुद्दों पर साफ दिखाई देती है। चीन जो आक्रामकता अब दिखा रहा है, इसकी पुष्टि भी उसकी बढ़ती ताकत और बेलगाम महत्वाकांक्षा है। यह भारत के लिए ही नहीं दुनिया के लिए भी चिंता का कारण बना हुआ है। सीमा विवाद सुलझाने में चीन की रुचि नहीं है। चीन भारत से इसलिए नाराज है, क्योंकि उसने जब तिब्बत पर कब्जा किया था, तब भारत ने तिब्बत के हमले दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बतियों को भारत में शरण दी थी। चीन की इच्छा है कि भारत दलाई लामा और तिब्बतियों द्वारा तिब्बत की आजादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई की खिलाफत करे।

दरअसल भारत ने तिब्बत को लेकर शिथिल व असमंजस की नीति अपनाई है। जब हमने तिब्बतियों को शरणार्थियों के रूप में जगह दे दी थी, तो तिब्बत को स्वतंत्र देश मानते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर समर्थन की घोषणा करने की जरूरत भी थी। डॉ राममनोहर लोहिया ने संसद में इस आशय का बयान भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश नीति के कारण नेहरू ऐसा नहीं कर पाए। इसके दुष्परिणाम भारत आज भी झेल रहा है। चीन

कूटनीति के स्तर पर भारत को हर जगह मात दे रहा है। पाकिस्तान ने 1963 में पाक अधिकृत कश्मीर का 5180 वर्ग किमी क्षेत्र चीन को भेंट कर दिया था। तब से चीन पाक का मददगार हो गया। चीन ने इस क्षेत्र में कुछ सालों के भीतर ही 80 अरब डॉलर का पूंजी निवेश किया है। झुबह अरब सागर पहुंचने की जुगाड़ में जुट गया है। इसी क्षेत्र में चीन ने सीधे इस्लामाबाद पहुंचने के लिए काराकोरम सड़क मार्ग भी तैयार कर लिया है। इस दखल के बाद चीन ने पीओके क्षेत्र को पाक का हिस्सा भी मानना शुरू कर दिया है। यही नहीं चीन ने भारत की सीमा पर हड़बे बनाने की राह में आखिरी बाधा भी पार कर ली है। चीन ने समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके गैलौला पर्वत पर 33 किमी लंबी सुरंग बनाकर इस बाधा को दूर कर दिया है। यह सड़क सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिब्बत में मोशुओ काउंटी भारत के अरुणाचल का अंतिम छोर है। अभी तक यहां सड़क मार्ग नहीं था। अब चीन इस मार्ग की सुरक्षा के बहाने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को सिविल इंजीनियर के रूप में तैनात करने की कोशिश में है। मसलन वह गिलगित और बलूचिस्तान में सैनिक मौजूदगी के जरिए भारत पर एक ओर दबाव की रणनीति को अंजाम देने के प्रयास में है। कूटनीतिक चाल चलते हुए नरेंद्र मोदी ने जब से बलूचिस्तान का समर्थन किया है, तबसे बलूच के विद्रोही लिबरेशन आर्मी और चीन द्वारा पाक में बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे का मुखर विरोध शुरू हो गया है। भूदान-भारत की सीमा पर डोकलाम विवाद भी कायम है। यह ठीक है कि भारत और चीन की सभ्यता 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। भारत ने संस्कृति के स्तर पर चीन को हमेशा नई सीख दी है। अब से करीब 2000 साल पहले बौद्ध धर्म भारत से ही चीन गया था। वहां पहले से कनफ्यूशियस धर्म था। दोनों को मिलाकर नवकनफ्यूशियसवाद बना। जिसे चीन ने अंगीकार किया। लेकिन चीन भारत के प्रति आंखें तरेरे हैं। इसलिए भारत को भी आंख दिखाने के साथ कूटनीतिक परिवर्तन की जरूरत है। भारत को उन देशों से मधुर एवं सामरिक संबंध बनाने की जरूरत है, जिनसे चीन के तनावपूर्ण संबंध हैं। ऐसे देशों में जापान, वियतनाम व म्यांमार हैं। चीन की काट के लिए भारत को तिब्बत, मंगोलिया व शिब्यांग के अल्पसंख्यकों को नथी बीजा देने की जरूरत है। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा।

■ प्रमोद नागित
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

हिंदी के महत्व को हम कब समझेंगे?

अबू धाबी ने अरबी व अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी कोर्ट में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। यह फैसला हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। इसकी अहमियत पूरी दुनिया में मानी जा रही है, पर हम स्टेटस का चोला उतारने को तैयार नहीं हैं।



संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। अबू धाबी में हिंदी भाषियों की तादाद काफी बड़ी है। इस फैसले का मकसद हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है। आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा विदेशों के प्रवासी लोग हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है जो देश की कुल आबादी का 30 फीसदी है व यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। हिंदी भाषियों को अबू धाबी न्यायिक विभाग की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अबू धाबी न्यायिक विभाग के अंडर सेफ्रेटरी यूसफ सईद अल आबरी ने कहा कि फैसले का मकसद न्यायिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना है।

संयुक्त अरब अमीरात का यह फैसला निश्चित रूप से हिंदी के प्रति पूरी दुनिया में बढ़ती स्वीकार्यता की अगली कड़ी है। हिंदी अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रमुखता से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। विदेशों में बसे भारतीयों की बढ़ती संख्या को अब संयुक्त राष्ट्र तक में मान्यता मिल चुकी है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में एक दृष्टिकोण कर यह बताने की कोशिश की थी कि इस भाषा का प्रभाव किस रूप में बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने हिंदी में भाषण दिया है। यह सिर्फ इसलिए ताकि अपनी मातृ भाषा का प्रचार-प्रसार हो सके। भारत आने वाले दुनिया भर के मेहमान चाहें वे राष्ट्र प्रमुख हों या फिर पर्यटक, हिंदी के प्रति प्रेम जाहिर करने से चूके नहीं। सभी के संबोधन में हिंदी का समावेश दिखा है। भले ही वह एक वाक्य या एक शब्द क्यों न हो। अब तक कई देशों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, तो कई विश्वविद्यालयों में हिंदी में पढ़ाई तक कराई जाने लगी है।

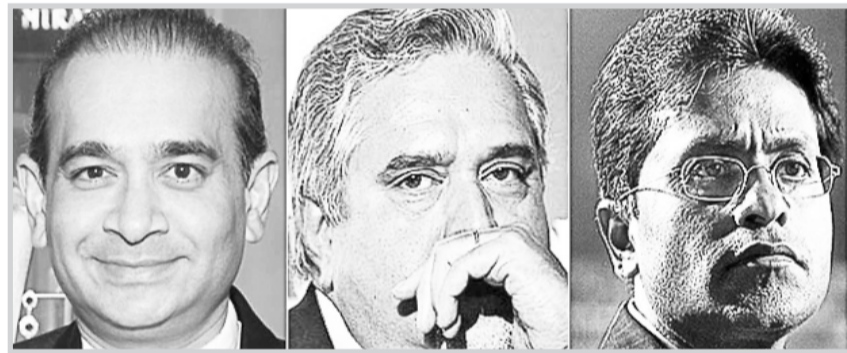
सरकार के प्रयासों से हिंदी को विश्वस्तार पर प्रतिष्ठापित जरूर किया जा रहा है, मगर एक सवाल भी है कि भारत में उसकी उपेक्षा कब तक होती रहेगी? देखा गया है कि भारत में जहां हिंदी मातृ भाषा है वहां अंग्रेजियत के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। भाषा को लेकर आम लोगों में ही नहीं, राज्यों के बीच भी तलवारें खिंची रहती हैं। भारतीय जनता की दुर्बलता एवं सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हिंदी को उसका उचित स्थान और सम्मान नहीं मिल पाया है। नेता हो या जनता-हिंदी की यह दुर्दशा एवं उपेक्षा सोचनीय है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह ऐसे आदेश जारी करे जिससे सरकार के सारे अंदरूनी काम-काज भी हिंदी में होने लगे और अंग्रेजी से मुक्ति की दिशा सुनिश्चित हो जाए। जब पूरी दुनिया हिंदी की अहमियत को मानने लगी है, तो हमें भी स्टेटस का चोला उतार फेंकना चाहिए।

आर्थिक भगोड़ों पर कसा शिकंजा

ब्रिटेन की ओर से विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश मिलना भारत सरकार की जितनी बड़ी उपलब्धि है उससे कहीं ज्यादा बड़ी सरकार से देशवासियों की उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें हैं कि सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां इसी तरह अन्य आर्थिक भगोड़ों को देश वापस आने, देश की पाई-पाई का हिसाब सूर समेत देने व उन्हें सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। हमारी एजेंसियां ऐसे लोगों को इतना विवश कर देंगी की वे विषय के किसी भी कोने में अपना मुंह न छिपाएं देश को लूट कर जाने वाले ऐसे आर्थिक भगोड़ों को हर कहीं से अपने देश जाने और यहाँ प्रत्यर्पण करने बाध्य होना पड़े। फिर वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी या मेहुल चोकसी इन भगोड़ों को भारत आकर अपना हिसाब देना होगा। विजय माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश पर ब्रिटेन के गृहमंत्री साजिद जावैद के हस्ताक्षर को भारत की कूटनीतिक जीत तौर पर भी देखा जाना चाहिए। लंदन की निचली अदालत में लंबी लड़ाई के बाद भारत को 10 दिवस के कामयाबी मिली थी।

लंदन के कोर्ट ने उस समय माल्या की सारी दलीलें खारिज कर दीं। माल्या के पक्ष में वहां बड़े-बड़े वकील जिद्द कर रहे थे। जब सारी दलीलें विफल हो गई तो मानवाधिकार का मुद्दा उठाया गया और बताया गया था कि भारत की जेलों में अमानवीय स्थिति है। इसमें भी भारत की जीत हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद से ही भारतीय विदेश मंत्रालय ब्रिटिश सरकार से संपर्क में था। इससे यह संदेश जाता है कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। हालांकि, माल्या का प्रत्यर्पण अब भी फलन नहीं हुआ है। उसके पास इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए दो हफ्ते का समय है। यदि अपील मंजूर नहीं होती है तो उसे हर हाल में 20 दिनों के भीतर भारत को सौंपना होगा। पर अब उच्च न्यायालय माल्या के पक्ष में कोई फैसला देगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिखता है। चूंकि निचली न्यायालय में मामला जमाना उलझाया जा सकता है उतना उच्च न्यायालय में नहीं।

यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि देश में माल्या की तरह विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की अच्छी खासी संख्या है। जिनसे यदि वक्तूरी की जाए तो रकम कई लाखों करोड़ों तक जा सकती है। माल्या के बाद नीरव मोदी जो 11 हजार 400 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा है और उसका साथी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की है। मेहुल ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। चोकसी पीएनबी घोटाले में वांचित है। उसने एंटीगुआ में भारतीय उच्चायोग को पासपोर्ट



ब्रिटेन की ओर से विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश मिलना भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अब उम्मीद यह भी जगी है कि देर-सबेर उन लोगों को भी भारत लाया जाएगा, जो देश का पैसा लेकर विदेशों में छिपे हैं। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने बड़ी बाधा पार कर ली है। यह नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी सहित दूसरे आर्थिक भगोड़ों के लिए कड़ा संदेश है।

के साथ ही 177 डॉलर का ड्राफ्ट भी सौंपा है। वहीं ललित मोदी पर 2008 से 2010 तक आईपीएल का कमिश्नर रहते भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने दो नई टीमें की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए और किसी लाभ के बदले एक पक्ष को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा मोदी ने आईपीएल का ठेका 425 करोड़ में मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स को दिया था। मोदी पर इस सौदे के बदले 125 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का भी आरोप है। इन आरोपों के बाद मोदी को वर्ष 2010 में आईपीएल कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। उसी साल वह देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गए। तब से भारत सरकार इन सबके प्रत्यर्पण की कोशिशें करने का दावा कर रही है। संजय भंडारी हथियारों के एक विवादित दलाल के तौर पर जाना जाता है। उस पर सेना के हथियार खरीद में गलत तरीके से शामिल होने के आरोप लागते रहे हैं। भंडारी और एक ऑफसेट कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में संजय भंडारी के आवास की तलाशी के दौरान आयकर विभाग को सेना के हथियारों की खरीद से संबंधित गोपनीय दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों में सैन्य साजो सामान के

खरीद के लिए बनाई गई अनुबंध समिति की बैठक के कुछ मिनट की प्रतियां भी थीं। इसी साल दिल्ली की एक अदालत ने के संजय भंडारी को सरकारी गोपनीय अधिनियम के मामले में घोषित अपराधी ठहराया है। बताया जाता है कि भंडारी नेपाल के रास्ते देश से भागने में कामयाब रहा है। बीते वर्ष मोदी सरकार ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ नया कानून बनाकर एजेंसियों को काफी मजबूती दी है। इसके तहत भगोड़ा घोषित होने के बाद उसकी विदेशों में संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। भारत सरकार ने इस कानून के तहत विजय माल्या को पहला भगोड़ा घोषित किया। उसकी विदेशी संपत्ति भी जब्त करने की कोशिश हो रही है।

मोदी सरकार के आर्थिक अपराध विधेयक 2018 के अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर निवेश न्यायालय द्वारा व्यक्ति की भारत में या भारत के बाहर कोई संपत्ति (जो अपराधी के स्वामित्व वाली है या नहीं और जो उसकी बेनामी संपत्ति है) उसे जब्त करने का आदेश देने का प्रावधान है। इस विधेयक में प्रावधान है कि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की रकम के ऐसे अपराध करने के बाद जो व्यक्ति फरार है या फिर भारत में दंडनीय

अभियोजन से बचने या उसका सामना करने के लिए भारत वापस आने से इंकार करता है, उसकी संपत्ति और अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है। इसमें किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की कोई सिविल दावा करने या बचाव करने की हकदारी नहीं होने का भी प्रावधान है। मोदी सरकार जब यह विधेयक ला रही थी तब विधेयक के उद्देश्यों में यह बात साफ की थी कि देश में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें लोग आर्थिक अपराध की दंडनीय कार्यवाही शुरू होने की संभावना में या कभी कभी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अदालतों के अधिकार क्षेत्र से पलायन कर गए हैं।

भारतीय अदालतों से ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति के अनेक हानिकारक परिणाम हुए और मामलों में जांच में बाधा उत्पन्न होती है। इससे न्यायालयों का समय व्यर्थ होता है और इससे विधि शासन तक कमजोर होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए और आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर बने रहने के माध्यम से भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने से हतोत्साहित करने के उपाय के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 अधिनियमित करने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि यह तमाम प्रक्रियाएं जितनी सहज और आसान दिखाई दे रही हैं यह उतनी ही कठिन हैं। केंद्र सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक तो ले आई पर चुनौतियों ने साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी चुनौती है दूसरे देशों के कानून व उन कानूनों के जरिए वहां की नागरिकता ले लेने वाले लोगों को मिली सुरक्षा से निपटना। यदि देखा जाए तो विजय माल्या के मामले में ये कानूनी पेचीदागी भी सामने आई हैं।

माल्या के पास विदेशी नागरिकता है जिस कारण वहां के कानून से मिली सुरक्षा कानूनी कार्रवाई में देरी का कारण बन रही है। नीरव मोदी भी नागरिकता का स्टेटस अनआरआई करवा चुका है। अब देश से फरारी के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं है। मोदी सरकार ये कानून विजय माल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों द्वारा बैंकों का अर्बों रुपए का कर्ज नहीं लौटाने और देश से बाहर चले जाने की पुष्टि में लेकर आई है। बहरहाल, यह सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि स्विट्जरलैंड सरकार ने माल्या के बैंक खातों की जानकारी देने पर भी सहमति दे दी है। देर-सबेर माल्या का भारत आना तथा उसकी संपत्तियां जब्त करना अब निश्चित हो गया है।

■ अक्षय नेमा मेख
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर



हिंदी की लोकप्रियता अब एक सीमा तक बंधी नहीं है। यह सात समुंदर पार तक पहुंच गई है। हमें भी चाहिए कि इस भाषा को पूरा मान दें और स्वीकार भी करें।

योगेंद्र यादव, विचारक

हिंदी की उपेक्षा कर हम अपना ही अहित कर रहे हैं। यदि हम अपनी भाषा को मान नहीं देंगे, तो दुनिया क्यों देगी? आज कई देश हिंदी को अपना रहे हैं, यह हमें संदेश है।



विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार

सत्यार्थ

सत्यार्थ



लिया, मगर वह लड़की तेज चलने के अस्थाय में जुट गई। वह अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने

संकल्प की ताकत

कुछ भी नहीं कह सकी। सारे विद्यार्थी उस पर देर तक हंसते रहे। अगले दिन खेल के पीरियड में उसे अलग बैठाया गया, तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियों हाथ में लीं व दृढ़ निश्चय के साथ बोली-सर, याद रखना, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों, तो सब कुछ संभव है। आप देख लेना, एक दिन यही लड़की सारी दुनिया को हवा से बातें करके दिखाएगी। उस वक्त सभी ने इसे मजाक के रूप में

लगी। फिर, वह कुछ दिनों में दौड़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसने छोटी-मोटी दौड़ में भाग लेना भी शुरू कर दिया। तभी कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसका हौसला बढ़ाया। बाद में उसने 1960 के ओलंपिक में हिस्सा लिया और तीन स्वर्ण पदक जीतकर सभी को हतप्रभ कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह लड़की थी, अमेरिकी धाविका विल्मा रडोल्फ। आशय यह है कि यदि इसान आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में जुट जाए, तो शारीरिक कमजोरी या फिर अपंगता भी उसके काम में बाधा नहीं बनती।

■ सुभाष गुड़गवतवाल

वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क पर 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना



नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के अपने नेटवर्क पर अगले 15 महीने के दौरान 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। कंपनी

के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वोडाफोन के मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मुद्रा ने विश्लेषकों से टेली-कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पूंजीगत खर्च के रूप में कुल 270 अरब रुपए दिए हैं। इसमें करीब 70 अरब रुपए पहले नौ महीनों में खर्च किए गए हैं। अगले 15 महीनों में 200 अरब रुपए का निवेश करने की योजना है। कंपनी

की राइट इश्यू के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। कंपनी के प्रवक्त शेरधरका वोडाफोन समूह और आदित्य बिड़ला समूह ने निदेशक मंडल की बैठक में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वह प्रस्तावित राइट इश्यू में अपनी हिस्सेदारी के तौर पर क्रमशः 11,000 करोड़ रुपए और 7,250 करोड़ रुपए तक का योगदान करने की मंशा रखते हैं। शेरधरका ने यह भी कहा कि यदि राइट इश्यू का कुछ हिस्सा नहीं

बिक पाता है तो वे उस बचे हुए हिस्से के पूरे या उसके कुछ भाग को खुद खरीदने का अधिकार अपने पास रख रहे हैं। मुद्रा ने विश्लेषकों से कहा कि 27,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में उस क्षमता को शामिल नहीं किया गया है। जो कि वोडाफोन और आइडिया के बीच परिचालन के तालमेल से उपकरणों को फिर से उपयोग में लाने से बनेगी। इस तरह की क्षमता का मूल्यांकन 6,200 करोड़ रुपए किया गया है।

आईएमएफ ने वृद्धि धीमी रहने पर वैश्विक आर्थिक 'बंवडर' उठने की दी चेतावनी

दुबई।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने रविवार को दुनिया भर की सरकारों को सावधान करते हुए आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कम रहने पर उठने वाले बंवडर का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगाई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में कहा, 'हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो अनुमान से भी कम रफ्तार से वृद्धि कर रही है।' आईएमएफ ने पिछले महीने ही इस साल की वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 3.7 प्रतिशत से

आईटीजी ने खोली अपनी वेबसाइट, पतंजलि को मिलेगी कड़ी टक्कर

विजनेस डेस्क।

रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनी (एफएमसीजी) में आगे निकले की होड़ में आईटीसी ने बड़ा कदम उठाया है। अब वह अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट लाएगी, जिससे उसके उत्पाद ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। कंपनी के एगिजक्यूटिव डायरेक्टर बी सुभ्रत ने बताया कि यह फैसला तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन कारोबार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि

कंपनी पहले से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर अपना सामान बेच रही है। हाल में आई नेलस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एफएमसीजी सेल्स में ई-कॉमर्स का शेयर पिछले दो सालों में तीन गुना बढ़ गया है। इस वक देश में करीब 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट है, जिसकी मदद से वह जरूरत की चीजों को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसे देखते हुए आईटीसी ने वेबसाइट लॉन्च की है। फिलहाल यह वेबसाइट दिल्ली-

एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में ही चलेगी। यहां सफल होने के बाद इस प्रयोग को आगे फैलाया जाएगा। पैकेजिंग फूड, पर्सनल केयर और स्टेशनरी के प्रॉडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों में आईटीसी 2030 तक भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। आईटीसी के वेबसाइट खोलने के कदम से बाबा रामदेव के ब्रैंड पतंजलि को कड़ी टक्कर मिल सकती है। पतंजलि पहले से वेबसाइट बनाकर पर उसपर अपने

उत्पाद बेच रहा है। हालांकि, साल 2018 उनके लिए भी खास अच्छा नहीं रहा। जीएसटी और कॉम्प्लिशन के चलते पिछले साल पतंजलि के बिजनेस को चोट पहुंची और 2013 के बाद उसने सबसे खराब प्रदर्शन किया था। रिसर्च प्लैटफॉर्म ट्रॉफर से मिले फाइनेंशियल डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 में पतंजलि की आमदनी 10 फीसदी गिरकर 8,135 करोड़ रुपए रह गई। जो सालभर पहले 9,030 करोड़ रुपए थी।

19 फरवरी से लागू हो जाएगा पैनिक बटन, इन महिलाओं को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली।

मुंबई में फंसी महिलाओं और बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए सरकार ऐतिहासिक डिजिटल कदम उठाने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 19 फरवरी से मोबाइल फोन में पैनिक बटन को अनिवार्य करने जा रहा है। यह बटन हर मोबाइल में होगा। आमतौर पर दो तरह के पैनिक बटन होते हैं जो मुंबई के वक बड़े काम के साबित होते हैं। करीब 3 साल पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव

पेश किया था। महिलाओं को किसी भी राज्य में सुरक्षा या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपात स्थिति आए तो वह अपने फोन में 112 नम्बर (पैनिक बटन) को डायल कर पुलिस की मदद मांग सकती है। इस नम्बर को दबाते ही नजदीक वाली पुलिस की मोबाइल वैन को स्वतः यह संदेश चला जाएगा कि किस जगह पर कोई महिला परेशानी में है। पैनिक बटन से आपात स्थिति में मदद के लिए महिला ने अपने जिन 5 करीबियों का फोन नम्बर रखा होगा, उनको भी संदेश मिल जाएगा। सबसे बेसिक पैनिक बटन किसी थैपट

अलार्म की तरह काम करते हैं। आपने बटन दबाया और सायरन की तरह जोरदार आवाज, आसपास के लोगों का ध्यान खींच लेती है और बटन दबाते ही मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सिस्टम को खड़ा करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कोष से 321 करोड़ रुपए दिए हैं। पैनिक बटन का एक राज्य में प्रयोग करके व्यावहारिक कठिनाइयों को समझा गया। प्रयोग सफल रहा, फिर भी कुछ समस्याएं बनी रहीं। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इसे तभी उपयोगी मानती थीं, ।

दुबई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने रविवार को दुनिया भर की सरकारों को सावधान करते हुए आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कम रहने पर उठने वाले बंवडर का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगाई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में कहा, 'हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो अनुमान से भी कम रफ्तार से वृद्धि कर रही है।' आईएमएफ ने पिछले महीने ही इस साल की वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 3.7 प्रतिशत से

घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया था। लगाई ने उन कारणों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की वजह बताया जिन्हें वह अर्थव्यवस्था के ऊपर मंडराने वाले 'चार बादल' बताती रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तूफान कभी भी उठ सकता है। उन्होंने कहा कि इन जोखिमों में व्यापारिक तनाव एवं श्रृंखला बढना, राजकोषीय स्थिति में सख्ती, बेविजत को लेकर अनिश्चितता तथा चीन की अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की रफ्तार तेज होना शामिल है। उन्होंने कहा कि विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं अमरीका और चीन के बीच जारी

श्रृंखला युद्ध का वैश्विक असर दिखने लगा है। उन्होंने सरकारों को संरक्षणवाद से बचने की सलाह देते हुए कहा, 'हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि यह किस तरह समाप्त होने वाला है और क्या यह व्यापार, भरोसा और बाजार पर असर दिखाने की शुरुआत कर चुका है।' लगाई ने कर्ज की बढ़ती लागत को भी जोखिम बताया।



संक्षिप्त समाचार

पायलट्स की कमी के कारण इंडिगो ने कैसल की 30 फ्लाइट्स

मुंबई। क्रिफायती विमान कंपनी इंडिगो ने देशभर में कई फ्लाइट्स कैसल करने की जानकारी दी है। इसके पीछे कू की कमी की बात सामने आई है। हालांकि, इंडिगो ने इस पर कुछ नहीं कहा है। हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर से ऑपरेट होने वाली बहुत सी फ्लाइट्स को शनिवार और रविवार को भी कैसल किया गया था, अब सोमवार को भी करीब 30 फ्लाइट्स कैसल होने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, चेन्नई से आठ, हैदराबाद से छह और जयपुर से तीन फ्लाइट्स को बीते शनिवार और रविवार को कैसल किया गया था। फ्लाइट कैसल होने के पीछे वजह बताते हुए एक सूत्र ने कहा, रोस्टर के हिसाब से पायलट्स को साल में 1 हजार घंटे से ज्यादा उड़ान नहीं भरवाई जा सकती। इंडिगो के कई पायलट्स अपनी लिमिटेड पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें फिलहाल उड़ान नहीं भरने दी जा सकती। हालांकि, इंडिगो ने पायलट्स की कमी पर कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि फ्लाइट खराब मौसम के चलते कैसल हुई है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा, शुक्रवार को उत्तर भारत में आए तूफान की वजह से इंडिगो की 11 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे ही काम करना पड़ा था। शेड्यूल को फिर से बनाने की वजह से कू और एयरक्राफ्ट की टाइमिंग में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

कोकोनिक्स ने लॉच किये भारत निर्मित लैपटॉप

नयी दिल्ली। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सुयुक्त उपक्रम कोकोनिक्स ने मेड इन इंडिया लैपटॉप लॉच करने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को यहां एमएआईटी द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शिखर सम्मेलन में इस लैपटॉप को लॉच किया जो चालू वर्ष की दूसरी तिमाही से बाजार में उपलब्ध होगा। कोकोनिक्स यूटीएस ग्लोबल, केलटॉन, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) और एक्सिलेरॉन लैब्स का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी का विनिर्माण संयंत्र तिरुवनंतपुरम में है। कंपनी ने तीन लैपटॉप प्रदर्शित किये जिसमें सीसी11बी, सीसी11ए और सी314ए शामिल हैं। ये लैपटॉप सरकारी संस्थानों, उद्यमों और शैक्षिक संस्थानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गये हैं। उसने कहा कि इसकी कीमतें प्रतिस्पर्धी रखी जायेंगी। इस शिखर सम्मेलन में 30 बड़ी कंपनियों के करीब 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

कार-बसों में इस्तेमाल होगा नया ईंधन, नहीं होगा प्रदूषण,

ग्रेटर नोएडा। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सीएनजी में हाइड्रोजन मिलाकर एचसीएनजी तैयार किया है जो वर्तमान इंजनों पर भी बीएस-6 उत्सर्जन के लगभग सभी मानकों को पूरा करेगा। आईओसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव सिंह ने रविवार को ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए तीन दिवसीय सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 में बताया कि कंपनी ने सीएनजी में 18 प्रतिशत हाइड्रोजन मिलाकर एचसीएनजी तैयार किया है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़कर अन्य सभी प्रदूषकों के मामले में भारत स्टेज-6 पर खरा उतरता है। देश में बीएस-6 अगले साल 01 अप्रैल से लागू होगा है। उन्होंने कहा, इस समय उर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। शेल गैस की प्रौद्योगिकी ने पिछले चार-छह साल में पूरे परिवर्तन को बदल दिया है। इससे कीमतों पर नकारात्मक असर जरूर पड़ा, लेकिन साथ ही दक्षता भी बढ़ी। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और प्रौद्योगिकी अज्ञानक सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सेक्टर को टिकाऊ उत्पाद पेश करना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो। मसलन आज के समय में यूरो-6 मानक वाले पारंपरिक वाहन इंजन सीएनजी इंजनों के समान ही कम प्रदूषण करने वाले हैं। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के छाने से पहले ही उनसे ज्यादा दक्ष पारंपरिक इंजन बाजार में आ जाएं। सिंह ने बताया कि एचसीएनजी तैयार करने की आईओसीएल की प्रौद्योगिकी का पेटेंट हो चुका है। जल्द ही दिल्ली में एक डीटीसी बस डिपो से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद इसका विस्तार किया जायेगा।

डॉलर के मुकाबले रुपये में बनी रही मजबूती

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये में सोमवार को भी मजबूती बनी रही। पिछले कारोबारी सत्र से आठ पैसे की बढ़त के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले 71.23 पर खुला। हालांकि वाद में रुपया थोड़ा फिसलकर 71.25 पर आ गया। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होने के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपये में यह तेजी देखा जा रही है। मुद्रा बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, विदेशी निवेश की आमद और कच्चे तेल के दाम में गिरावट से रुपये को सपोर्ट मिला है। उधर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी रहने की आशंकाओं से डॉलर में निवेश के प्रति निवेशकों का रूझान बढ़ने से डॉलर प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है।

2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम



बिजनेस डेस्क। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सोमवार को फिर से बढ़ोतरी हुई। दो दिनों की गिरावट के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज 5 पैसे महंगा हुआ और डीजल में भी 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इसका असर दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनियाभर की आर्थिक ग्रोथ को लेकर जारी चिंता का असर कच्चे तेल पर है। अगर दुनिया में आर्थिक ग्रोथ धीमी रहती है तो मैनुफैक्चरिंग और अन्य गतिविधियां भी धीमी हो जाएंगी। लिहाजा कच्चे तेल की डिमांड में कमी आएगी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 70.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत में 72.44 रुपए प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 75.97 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 73.00 रुपए प्रति लीटर पर है। डीजल की कीमतें दिल्ली 65.62, कोलकाता में 67.40, मुंबई में 68.71 और चेन्नई में 69.32 रुपए प्रति लीटर पर बनी हुई हैं।

मात्र 53 महीनों में जन धन खातों में जमा हो गए करीब 90,000 करोड़ रुपए

नई दिल्ली।

करीब 53 महीने पहले शुरू हुई जन धन खाता योजना के खुले हुए खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। वित्त मंत्रालय की मानें तो जल्द ही इन खातों में 1 लाख करोड़ रुपए पार हो जाएंगे। इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर को दोगुना करने के बाद इन खातों में जमा राशि और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद यह बात सामने आई। खासकर मार्च 2017 से जन धन खातों में जमा

में तेजी आई है। इन खातों में 30 जनवरी 2019 तक कुल जमा बढ़कर 89,257.57 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जमा में वृद्धि जारी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से जन धन खातों के आंकड़े जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 23 जनवरी को जन धन खातों में कुल जमा 88,566.92 करोड़ रुपए था। इस योजना की सफलता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को एक

लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। वहीं ओवरड्राफ्ट की सीमा को दोगुना करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केन्द्र ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 34.14 करोड़ खाते खोले गए हैं। इन खातों में औसत जमा बढ़कर 2,615 रुपए हो गया, जो 25 मार्च 2015

को 1,065 रुपए पर था। इन खातों में 53 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, जिनमें से 59 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र से हैं। आंकड़ों के मुताबिक 27.26 करोड़ खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डैबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस में देना होगा खाने का चार्ज,

नई दिल्ली। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 में यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ उनके टिकट का हिस्सा होगा। यानी वह इसे विकल्प की तौर पर 'चुन या हटा' नहीं सकते हैं, जैसा कि शताब्दी, राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस में होता है। अधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को यह जानकारी दी। हालांकि इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से इलाहाबाद से वाराणसी की यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक करने के दौरान खाद्य पदार्थ चुनने या नहीं चुनने की सुविधा होगी। यह भोजन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की ओर से मुहैया कराया जाएगा। कैटरिंग शुल्क उनके टिकट में शामिल नहीं होगा। यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा 15 फरवरी को शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि यात्री अगर टिकट बुक करने के दौरान भोजन का विकल्प नहीं चुनते हैं, लेकिन वह यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थ चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त 50 रुपये देने होंगे। आईआरसीटीसी ने 2017 में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में पैंटी सिंक्स बैकल्पिक कर दिया था। ऐसा यात्रियों से ज्यादा शुल्क वसूलने और गुणवत्ता तथा मात्रा की समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था। वहीं ट्रेन 18 के बारे में एक अधिकारी ने कहा, 'स्टेशनों के बीच कैटरिंग शुल्क तय कर दिया गया है और यह सभी यात्रियों के टिकट शुल्क में जोड़ा जाएगा।' ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया प्रीमियम ट्रेनों के मुकाबले अधिक होगा। ट्रेन अपनी 755 किलोमीटर की यात्रा में दो स्टेशनों कानपुर और प्रयागराज में रुकेगी।



फंसे घर बनाने के लिए केंद्र सरकार देगी आर्थिक मदद, आम्रपाली पर होगा फोकस



विजनेस डेस्क।

आम्रपाली समेत दूसरे बिल्डिंगों से घर खरीदकर अगर आप भी फंसे गए हैं तो आपके लिए बड़ी राहत है। केन्द्र सरकार इन डूबी आवासीय परियोजनाओं को उबारने की योजना पर काम कर रही है। सरकार बैंकों के माध्यम से करीब 1,000 करोड़ रुपए बतौर संकट निधि (स्ट्रेस फंड) मुहैया

करवाएगी। अगले दो सप्ताह में यह फैसला होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आम्रपाली पर फोकस कर रही है। आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक पर आए संकट से करीब एक लाख खरीदारों को उबारने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति का गठन किया

था। समिति ने सरकार को पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों के माध्यम से आर्थिक मदद दे। अब इस मसले में तेजी आई है। शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर 2 फरवरी को बैठक हो चुकी है। खरीदारों की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि उन्हें मंत्रालय के उच्चस्तरीय अधिकारी ने बताया कि स्ट्रेस फंड देने के लिए सहमति बन चुकी है। जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। सबसे पहले आम्रपाली बिल्डर के डूबे प्रोजेक्ट उबारे जाएंगे। फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम

कोर्ट में सुनवाई होगी। खरीदारों का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि सरकार को स्ट्रेस फंड देने के लिए आदेश दें। अब तो आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। खरीदार भी आ रहे हैं। अब अगर सरकार स्ट्रेस फंड देती है तो उसका पैसा आसानी से निकल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) बिल्डर की संपत्तियों को नीलाम करके पैसा अर्जित कर रहा है। यह पैसा एनबीसीसी को देकर अर्धूरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया जाएगा। खरीदार करीब दो वर्षों से स्ट्रेस फंड देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि अंततः बजट में सरकार प्रावधान करेगी। लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। तब से खरीदार कड़ी नाराजगी जता रहे हैं।

विदेश में इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट पर आयकर विभाग की नजर



मुंबई।

विदेश में शेयरों और प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले या विदेशी ट्रस्टों के बनेफिशियरी में शामिल अमीर भारतीयों की ओर आयकर विभाग

की नजर घूमि है। विभाग उनसे जानना चाहता है कि अपने इन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट्स की जानकारी इन लोगों ने क्यों नहीं दी। अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी कंपनी में स्ट्रेकहोल्डर हो और वह कंपनी दूसरी विदेशी कंपनियों में निवेश करे तो ऐसा निवेश भारतीय

व्यक्ति का इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर किसी शख्स की दुबई में किसी अर्नलिस्टेड विदेशी कंपनी ए में 15 प्रतिशत हिस्सा हो और वह कंपनी तीन अमेरिकी कंपनियों बी, सी और डी में शेयरहोल्डर हो, तो टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बी, सी और डी में इनडायरेक्ट ओनरशिप का खुलासा इनकम टैक्स रिटर्न में

कंपनी ए में किए गए निवेश की जानकारी देने के साथ किया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से सवाल किया है कि उन्होंने अपने इनडायरेक्ट इनवेस्टमेंट की जानकारी क्यों नहीं दी, जबकि कानून के मुताबिक बतौर इंडियन रेजिडेंट वे सभी कंपनियों के अल्टीमेट बनेफिशियल ओनर हैं।

ऐसी जानकारी न देने पर कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर टैक्स डिपार्टमेंट जवाब से संतुष्ट हो तो वह ब्लैक मनी से जुड़े नए कानून के तहत कदम उठ सकता है। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप लखानी ने कहा, बनेफिशियल ओनरशिप की परिभाषा देने के लिए इनकम टैक्स

ऐक्ट के सेक्शन 139 को बदला गया था। इनडायरेक्ट ओनरशिप को भी इस परिभाषा के दायरे में लिया गया है। यह परिभाषा पहली अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। भारत से बाहर किसी स्ट्रक्चर में किए गए ऐसे निवेश को इसमें कवर किया गया है, जिससे बाद में दुनिया में कहीं भी दूसरे स्ट्रक्चर में निवेश किया गया हो।



सूरत। मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के अंतर्गत शहर भाजपा अध्यक्ष नीतीनभाई भजीयावाला ने अपने घर पर भाजपा का ध्वज लहराया। भाजपाध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद में मेरा परिवार-भाजपा परिवार के राष्ट्रव्यापी अभियान का प्रारंभ कराया।

मेरा परिवार-भाजपा परिवार अभियान का शुभारंभ

एक बार मोदी सरकार के हमारे संकल्प को साकार करे

सक्षम संगठन और मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व का त्रिवेणी संगम २०१९ का लोकसभा इतिहास बनायेगा : शाह



अहमदाबाद। मंगलवार को अहमदाबाद के थलतेज क्षेत्र में हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे के साथ खुद के आवास पर भाजपा का झंडा फहराकर तथा स्टीकर लगाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 'मेरा परिवार-भाजपा परिवार' के अभियान का प्रारंभ कराया। 'मेरा परिवार-भाजपा परिवार' अभियान के देशव्यापी शुभारंभ के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ओडिटोरियम में बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि, २०१९ के लोकसभा चुनाव अभियान का पहला कार्यक्रम 'मेरा परिवार-भाजपा परिवार'

का मंगलवार से शुभारंभ हो रहा है। देशभर के ५ करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता कमल के चिह्न के साथ अपने घर पर झंडा लगाकर कुल २० करोड़ से ज्यादा मतदाता भाजपा तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। गत चुनाव में १७.५ करोड़ मतदाता के समर्थन के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था। इस बार यह अभियान की शुरुआत में ही २० करोड़ मतदाता के साथ हमें सीधा संपर्क स्थापित कर रहे हैं। संगठन की शक्ति जागरूक करके इसमें जीत में परिवर्तित करने का यह कार्यक्रम है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में ही एक घंटे में १ लाख से ज्यादा लोगों ने भाजपा के झंडे को स्थापित किया है। संगठन के चार कार्यक्रम 'मेरा परिवार भाजपा परिवार महासंपर्क अभियान,

कमलज्योति तथा विजय संकल्प रैली की श्रृंखला द्वारा देश की जनता, गरीब, पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा की जीत को एक विजयमाला के संकलित मणका बनाने का यह संगठनलक्षी पर्व है। पिछले पांच वर्ष में भाजपा तथा एनडीए शासित १६ राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा अभूतपूर्व जनकल्याण के कार्य हुए हैं। ६ करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना द्वारा निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की बात हो या २.५ करोड़ जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना हो, या २.५ करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना द्वारा बिजली पहुंचाना हो या ८ करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराकर महिला के सम्मान बढ़ाने का कार्य करना हो यह सभी कार्य दूरदराज के

लोग अंत्योदय को लेकर भाजपा के शासन में हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता करके ५० करोड़ देशवासियों के लिए आयुष्मान योजना द्वारा पांच लाख तक का बीमा भी भाजपा सरकार ने उपलब्ध कराया है। पार्टी की भावना यह है कि जो लाभार्थी हुए हैं इसके अलावा दूसरे करोड़ों लोगों को यह लाभ पहुंचाने का है। ७० वर्ष में से ५५ वर्ष जो कांग्रेस के शासन में दलित, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित थे उनको नरेन्द्र मोदी की सरकार में जो लाभ मिला है ऐसे २५ करोड़ लाभार्थी के लिए हमें कमलज्योति द्वारा विकास की दिवाली एक ही दिन २६ फरवरी, २०१९ को मनायेंगे। विजय संकल्प रैली द्वारा पूरे

राजेश भारूका बने अस्मिता सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष

सूरत। अस्मिता सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा संघ ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग भटार रोड पर सूरत में आयोजित की गयी जिसमें राजेश भारूका सूरत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया। भारूका, वैश्य समाज, अग्रवाल समाज, गौ सेवा सहित अन्य बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भारूका ने संघ ने राष्ट्रीय सेवा संघ द्वारा आगामी समय में की जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए कहा की संघ विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगा। जिससे देश की करोड़ों विधवा बहनों को रोजगार के अवसर प्रदान करवाना, बेटी बचाओ बेटी

पदाओं के लिए कार्य किया जाएगा। दिव्यांग के लिए विशेष रूप से कार्य करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। केन्द्र एवम् राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करके उन्हें लाभान्वित करने में सहयोग करना। आगामी मार्च माह में महिला दिवस पर राष्ट्रीय सेवा संघ के माध्यम से स पूरा देश में महिला सशक्तिकरण के कार्य किए जाएंगे। आगे राजेश भारूका ने जानकारी देते हुए बताया की ट्रस्ट द्वारा नर सेवा नारायण सेवा कि मूल भावना के साथ स पूरा देश में कार्य किया जाएगा। मार्च महीने में आयोजित महिला दिवस पर स पूरा देश में महिला सशक्तिकरण के कार्य किए जाएंगे।

छत्रपति शिवाजी जयंती के दिन छुट्टी की मांग

सूरत। सांस्कृतिक रक्षा समिति द्वारा छत्रपति शिवाजी जयंती के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की गयी। हिन्दू स्वराज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती 19 फरवरी को है। इस दिन पूरे देश में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करने की मांग सांस्कृतिक समिति द्वारा की गयी। इस समिति के आशिय सुर्यवंशी ने बताया कि सांस्कृतिक रक्षा समिति ने सूरत कलक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा गुजरात के मुख्यमंत्री को लिखित में पेशकश की है। इस आवेदन में कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र तथा कुशल राजनीति जैसी अनेक विशेषताएं छात्रों के पठन के लिए



पाठ्यपुस्तक में समावेश करना चाहिए। 13 फरवरी से सूरत कलक्टर कार्यालय के बाहर धरना करेंगे। जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, युथ फॉर गुजरात और छोटी-बड़ी कुल 400 संस्थाएं समर्थन देंगी।

महावीर टेक्सटाइल मार्केट के गेट के पास सिक्क्युरिटी गार्ड की रहस्यमयी मौत कान और माथे में से निकल रहा था खून, मोबाईल गायब

सूरत। मंगलवार की सुबह रिंगरोड महावीर मार्केट के गेट के पास सिक्क्युरिटी गार्ड मृत हालत में मिला जिसकी सुचना सलाबतपुरा पुलिस को दी गई। सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के कान और माथे में खून निकल रहा था और उसका मोबाईल उसके पास नहीं था, जिससे लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सलाबतपुरा पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह रिंगरोड महावीर

मार्केट के पास हनुमान मंदिर के सामने सिक्क्युरिटी गार्ड मृत हालत में पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही सलाबतपुरा डी स्ट्राफ के पीएसआई कुशवाह घटना स्थल पर पहुंच कर लाश का पंचनामा किया। मृतक रामउजागर चंद्रपाल तिवारी उम्र 55, राधाकृष्णा सोसायटी, आशीर्वाद टाउनशिप के पास 120 फूट रोड बमरोली 5 संतानों के पिता है वे पिछले 8 से 9 महीने से सिक्क्युरिटी एजेन्सी में काम कर रहे थे।

पिछले 2-3 दिन से सिक्क्युरिटी एजेन्सी द्वारा रामउजागर को महावीर मार्केट के पास ड्युटी सोंपी गई थी। रामउजागर की मौत किस कारण हुई इसका पता तो पोस्ट मार्टम के बाद ही लग पाएगा। हाल में पुलिस अकस्मात मौत का केश दाखिल कर तपास कर रही है। रामउजागर के कान और माथे में से खून निकल रहा था और उसका मोबाईल भी गायब था इससे तो लूट के इरादे से हत्या की गई हो इसकी आशंका जताई जा रही है।

गुजरात में पहली बार १२ ज्योतिर्लिंग की रथयात्रा सोमनाथ में २३-२५ दौरान द्वितीय द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोह होंगी

अहमदाबाद। विश्वभर में प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव रत्नाकर सागर तट पर बिराजमान सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है। भारत के शिव आस्था के केंद्र समान १२ ज्योतिर्लिंग शिवालय के ट्रस्टी, कई पूजारी, तीर्थ पुरोहित और विकास कार्यों के साथ जुड़े हुए भक्तों और कई दाता का समारोह गत वर्ष उज्जैन महाकालेश्वर में आयोजित किया गया। इस वर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य और ऐतिहासिक समारोह २३, २४ और २५ फरवरी के दौरान सोमनाथ प्रभासपाटण में आयोजित किया जाएगा। जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित के कई महानुभाव पहुंचेंगे। यह द्वितीय द्वादश ज्योतिर्लिंग

समारोह के तहत गुजरात राज्य में पहली बार १७ से २१ फरवरी के दौरान राज्य के ३३ जिलों में सोमनाथ सहित १२ ज्योतिर्लिंग के रथ और झांखी तैयार किया गया है, यह राज्य के तीन-तीन जिलों में घूमकर भक्तों और नागरिकों में १२ ज्योतिर्लिंग के इतिहास सहित की धार्मिक जागरूकता लायी जाएगी यह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष केशुभाई पटेल और ट्रस्ट के सेक्रेटरी पीके. लहेरी ने बताया। उन्होंने आगे बताया है कि, गुजरात में सोमनाथ के परिसर में २३ से २५ फरवरी के दौरान बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महोत्सव द्वितीय द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें

१२ ज्योतिर्लिंग के ट्रस्टी, कई पूजारी, तीर्थ पुरोहित, पंडितों, साधु-संत विशेष रूप से पहुंचेंगे। यह भव्य धार्मिक महोत्सव की गुजरातभर में भव्य तरीके से मनाया जाए इसके लिए गुजरात के ३३ जिलों में सोमनाथ सहित के १२ ज्योतिर्लिंग के कुल १२ रथ तैयार किए गए हैं। यह रथ राज्य के तीन-तीन जिलों में १७ से २१ फरवरी के दौरान घूमेंगी और लोगों को शिवभक्ति, १२ ज्योतिर्लिंग का महात्म्य, इतिहास और भारतीय संस्कृति-नीति की जागरूकता लाने के लिए सभी रथ अलग-अलग जगहों से २२ तारीख को सोमनाथ में पहुंचेंगी। इसके बाद २३ तारीख को प्रभासपाटण में यह रथों की बहुत बड़ी और लंबी एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।



कांग्रेस पार्टी ने बजट में कराये गये आवंटन के खर्च के विरुद्ध प्रश्न उठाये।

भाजपा में आए चेतन ठाकोर ने की भाजपा के विरुद्ध बगावत

अहमदाबाद। शहर के खाडिया क्षेत्र में १९८५ में हुए दंगों के दौरान कॉन्स्टेबल लक्ष्मण देसाई की हत्या के सनसनी केस में भाजपा के नेता और कॉर्पोरेटर मयूर दवे सहित पांच लोगों को यहाँ के एडिशनल सेशन जज ए.आर. पटेल ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा निर्दोष बरी किया गया। कोर्ट द्वारा निर्दोष ठहराये गये अन्य लोगों में पूर्व मंत्री बीमल शाह के भाई किरण शाह, परेश शाह, एडवोकेट और भाईयो में मधुकर व्यास, ध्रुवकुमार व्यास शामिल हैं। सेशन कोर्ट ने आशंका का लाभ देकर सभी आरोपियों को निर्दोष ठहराकर बरी करने का आदेश दिया गया। यह केस की यह जानकारी है कि, वर्ष

१९८५ के दंगों के समय अप्रैल महीने के दौरान शहर के खाडिया क्षेत्र में कॉन्स्टेबल लक्ष्मण देसाई तथा अन्य एक पुलिस कर्मचारी को हिंसक भीड़ ने हमले का शिकार बनाया था। जिसमें कॉन्स्टेबल लक्ष्मण देसाई को पेट में गुप्ती के वार कर देने से गंभीर रूप से घायल होने की वजह से मौत हो गई थी। इस केस में तत्कालीन डीसीपी महापात्र द्वारा भाजपा के पूर्व सांसद हरिन पाठक और पूर्व स्वास्थ्यमंत्री अशोक भट्ट, भाजपा के कॉर्पोरेटर मयूर दवे सहित कुल ११ आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस सनसनी केस में भाजपा के पूर्व सांसद हरिन पाठक और पूर्व स्वास्थ्यमंत्री अशोक भट्ट को गुजरात हाईकोर्ट ने

डिस्चार्ज कर दिया था, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर रखा था। जिसकी वजह से वह इस केस में कोई आरोप नहीं बनने से बरी हो गये थे। जबकि चार आरोपी केस चलने के दौरान निधन हो गया था और बाद में मयूर दवे सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध केस चला था। जिसमें बचाव पक्ष बचावपक्ष की तरफ से सीनियर वकील एचएम. ध्रुव और चेतन शाह ने महत्व की दलीलें देते हुए कहा कि, यह पूरे केस में शिकायतकर्ता डीसीपी महापात्र सहित के गवाह आरोपियों को नहीं पहचान सके। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह केस साबित नहीं हुआ है। इस केस में आरोपीपक्ष के विरुद्ध में कोई निश्चित सबूत पेश नहीं हुए हैं।